

## “एक राष्ट्र, एक चुनाव” 129वाँ संवधान संशोधन वधियक 2024

### प्रलम्बिस के लयि:

129वाँ संवधान संशोधन वधियक, 2024 की मुख्य वशिषताएँ, [संवधान संशोधन वधियक](#), [लोकसभा](#), [राष्ट्रपति](#), [जम्मू-कश्मीर पुनरगठन अधिनियम, 2019](#)

### मेन्स के लयि:

वधियक की मुख्य वशिषताएँ, भारत में एक राष्ट्र, एक चुनाव के नहितारथ

[स्रोत: पी.आई.बी](#)

### चर्चा में क्यो?

हाल ही में, सरकार ने [लोकसभा](#) में दो [संवधान संशोधन वधियको](#) “एक राष्ट्र, एक चुनाव”-‘129वाँ संवधान संशोधन वधियक, 2024’ और ‘केंद्रशासित प्रदेश कानून संशोधन वधियक, 2024’ को पेश करके “एक राष्ट्र, एक चुनाव” को लागू करने की दशा में बड़ा कदम उठाया है।

- भारत में वर्ष 1951 से 1967 तक लोकसभा और सभी राज्य वधानसभाओं के चुनाव एक साथ आयोजित किये गए थे।

### वधियक की मुख्य वशिषताएँ क्या हैं?

- ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ 129वाँ संवधान संशोधन वधियक 2024: वधियक में लोकसभा और राज्य वधानसभाओं के कार्यकाल को संरक्षित करने के लिये पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोवदि की अध्यक्षता वाली समिति की सफारिश पर संवधान में **अनुच्छेद 82A (1-6)** को जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया है।
  - **अनुच्छेद 82 (1-6):**
    - **82A (1)** में राष्ट्रपति द्वारा आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक की तिथि में प्रस्तावित परिवर्तनों को लागू करने के लिये समय-सीमा का प्रावधान किया गया है, जिसे “नियत तिथि (Appointed Date)” के रूप में नरिदष्टि किया गया है।
  - धारा 82(2) में कहा गया है कि **नियत तिथि के बाद और लोक सभा का पूर्ण कार्यकाल समाप्त होने से पहले** नरिवाचति सभी **राज्य वधानसभाओं का कार्यकाल** लोक सभा के कार्यकाल के साथ समाप्त हो जाएगा।
    - **अनुच्छेद 82A (3)** में कहा गया है कि **भारत का नरिवाचन आयोग (ECI)** लोकसभा और सभी वधानसभाओं के लिये **एक साथ आम चुनाव** कराएगा।
    - **अनुच्छेद 82A (4)** एक साथ चुनावों को “**लोकसभा और सभी वधानसभाओं के एक साथ गठन के लिये आयोजित आम चुनाव**” के रूप में परभाषति करता है।
    - **अनुच्छेद 82A (5)** **भारत का नरिवाचन आयोग** को लोकसभा चुनाव के साथ किसी वशिष वधानसभा चुनाव न कराने का विकल्प प्रदान करता है।
      - भारत का नरिवाचन आयोग **राष्ट्रपति को किसी वधान सभा के लिये बाद में चुनाव कराने** की अनुमति देने हेतु आदेश जारी करने की सलाह दे सकता है।
    - **अनुच्छेद 82A (6)** में कहा गया है कि यदि किसी वधानसभा का चुनाव **स्थगित** कर दिया जाता है तो उस वधानसभा का **पूर्ण कार्यकाल भी** आम चुनाव में नरिवाचति लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल के साथ समाप्त हो जाएगा।
  - **अनुच्छेद 83 और 172 में संशोधन:**
    - वधियक के अनुसार, यदि लोकसभा अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग हो जाती है, तो अगली लोकसभा **केवल शेष अवधितक ही कार्य करेगी, जिसे “वधितन की तिथि और पहली बैठक की तिथि से पाँच वर्ष के बीच की अवधि”** के रूप में परभाषति किया गया है।
      - इसका अर्थ यह है कि सदन के **पूर्ण कार्यकाल तक चलने के बाद भी, जो वधियक अभी भी लंबति है, उनकी समय-सीमा समाप्त हो जाएगी।**
    - राज्य वधानसभाओं के लिये अनुच्छेद 172 में संशोधन प्रस्तावित किया गया है, जो राज्य वधानसभाओं की अवधि को नरिंतरति करता है।
      - यदि किसी राज्य वधानसभा को उसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले **भंग कर दिया जाता है, तो पछिली वधानसभा के शेष**

कार्यकाल के लिये चुनाव कराए जाएंगे।

- अनुच्छेद 372 में संशोधन:
  - वधियक में अनुच्छेद 372 में संशोधन का प्रस्तावति है, जिसमें "नरिवाचन क्षेत्रों के परसीमन" के बाद एक साथ चुनाव कराने को शामिल किया जाएगा, जिससे राज्य वधियन सभा चुनावों पर संसद की शक्तिका वसितार होगा।
    - इस वधियक में स्थानीय नकियों और नगर पालकियों के चुनाव को शामिल नहीं किया गया।
- केंद्रशासति प्रदेश कानून संशोधन वधियक 2024:
  - वधियक का उद्देश्य संघ राज्य क्षेत्र शासन अधनियम, 1962 की धारा 5, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दलिली शासन अधनियम, 1991 की धारा 5 तथा जममू-कश्मीर पुनरगठन अधनियम, 2019 की धारा 17 में संशोधन करना है, ताकलोकसभा और राज्य वधियनसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जा सकें।

## भारत में चुनाव से संबंधति संवैधानकि प्रावधान क्या हैं?

- भाग XV (अनुच्छेद 324-329): यह चुनाव और उनसे संबंधति मामलों के लिये आयोग की स्थापना के प्रावधान से संबंधति है।
- अनुच्छेद 324: यह नरिवाचन आयोग को संसद और राज्य वधियनसभाओं के चुनावों की संपूर्ण प्रक्रिया का पर्यवेक्षण, नरिदेशन तथा नरियंत्रण करने का अधिकार देता है।
- अनुच्छेद 325: इसमें लोकसभा और राज्य वधियनसभाओं के सभी चुनावों के लिये एकल नरिवाचक नामावली की स्थापना का प्रावधान करता है।
- अनुच्छेद 326: यह नरिदषिट करता है कलोकसभा और राज्य वधियनसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार पर आधारति होंगे।
- अनुच्छेद 82 और 170: ये नषिपक्ष प्रतनिधितिव सुनश्चिति करने के लिये प्रत्येक जनगणना के बाद नरिवाचन क्षेत्रों का परसीमन अनविर्य कयि जाने से संबंधति हैं।
- अनुच्छेद 172: इसके अनुसार प्रत्येक राज्य की प्रत्येक वधियनसभा, यदापहले ही वधितति नहीं कर दी जाती है तो, अपने प्रथम अधविशन के लिये नयित तारीख से पाँच वर्ष तक बनी रहेगी।

## 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पर उच्च स्तरीय समति की रपिर्त

- समति का गठन और उद्देश्य:
  - पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोवदि की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समति का गठन केंद्र सरकार द्वारा सतिंबर 2023 में कयि गया था।
  - समति को लोकसभा, राज्य वधियनसभाओं और स्थानीय नकियों के लिये एक साथ चुनाव कराए जाने की व्यवहार्यता की जाँच करने का कार्य सौंपा गया था।
- एक साथ चुनाव कराए जाने का औचित्य:
  - समति ने स्पष्ट कयि कबार-बार चुनाव कराए जाने से अनश्चितता की स्थति उत्पन्न होती है, जबकि एक साथ चुनाव कराए जाने से स्थरि शासन सुनश्चिति होगा और व्यवधान कम होंगे।
    - इसके अतरिकित, एक साथ चुनाव कराए जाने से लागत में कमी आने और मतदाता की सहभागति बढ़ने की उम्मीद है।
- नरिवाचक नामावली प्रबंधन:
  - नरिवाचन प्रक्रिया को सुव्यवस्थति करने के लिये समति ने राज्य नरिवाचन आयोगों (SEC) के परामर्श से भारत के नरिवाचन आयोग (ECI) द्वारा तैयार एकल नरिवाचक नामावली के अंगीकरण का सुझाव दयि।
    - इससे दोहराव कम होगा और नरिवाचन के प्रबंधन में शामिल वभिन्न एजेंसियों की कार्यकुशलता में सुधार होगा।
- रसद व्यवस्था:
  - समति ने इस बात पर ज़ोर दयि कECI और SEC दोनों को एक साथ होने वाले चुनावों के दौरान सुचारु क्रयान्वयन सुनश्चिति करने के उद्देश्य से रसद व्यवस्था करने हेतु वसितृत आयोजना और उसका आकलन करना चाहयि।

## एक साथ चुनाव कराए जाने से संबंधति चुनौतियाँ क्या हैं?

- बुनयादी ढाँचे का वकिस: एक साथ चुनाव कराए जाने की जटलिताओं से नपिटने के लिये तकनीकी बुनयादी ढाँचे की पर्याप्त उपलब्धता सुनश्चिति करना महत्त्वपूर्ण है।
  - इसमें इलेक्ट्रॉनिकि वोटगि मशीन (EVM) और वोटर वेरफिएबल पेपर ऑडिट टरेलस (VVPAT) का प्रभावी परनियोजन और प्रबंधन शामिल है।
  - 2024 के आम चुनावों में, समग्र देश के 1.05 मिलियन मतदान केंद्रों पर लगभग 1.7 मिलियन नरियंत्रण एकक और 1.8 मिलियन VVPAT प्रणालियों का परनियोजन कयि गया था।
- वधिकि चुनौतियाँ: कसी भी संशोधन और एक साथ चुनाव क्रयान्वति करने की प्रक्रिया को वधिकि चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और संवैधानकि प्रावधानों के अनुपालन को सुनश्चिति करने के लिये नयायकि जाँच की आवश्यकता हो सकती है।
- क्षेत्रीय असमानताएँ: कुछ राजनीतिक दलों का मत है कएक साथ चुनाव कराए जाने से राष्ट्रीय अभयान के दौरान क्षेत्रीय हतियों और मुद्दों की उपेक्षा हो सकती है।
  - वविधि प्रतनिधितिव बनाए रखने हेतु यह सुनश्चिति करना महत्त्वपूर्ण है कस्थानीय मुद्दे राष्ट्रीय हतियों से प्रभावति न हों।
- प्रशासनकि चुनौतियाँ: वभिन्न राज्यों में एक साथ चुनाव आयोजति करने से अनेक चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं, जनिमें मतदाता सूचियों का प्रबंधन

और सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है।

- नागरिकों को नई नरिवाचन प्रक्रिया और उसके नहितार्थों के बारे में जानकारी देने के लिये एक व्यापक मतदाता शिक्षा अभियान की आवश्यकता होगी।

## एक साथ चुनाव कराने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिये कौन-सी रणनीति अपनाई जा सकती है?

- **वधिक स्पष्टता:** एक साथ चुनाव कराने के लिये स्पष्ट नरिदेश स्थापित करना, मतदाता पंजीकरण के लिये कार्यक्रम और प्रक्रियाओं का वविरण देना।
  - सरकार के सभी स्तरों पर चुनावों के समन्वयन को सुगम बनाने के लिये आवश्यक संवैधानिक संशोधन को सुनिश्चित किये जाने चाहिये।
- **चुनावी बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करना:** कोवदि समिति की सफ़िरशि के अनुसार, एक ऐसी एकीकृत मतदाता सूची प्रणाली वकिसति की जानी चाहिये, जो सरकार के तीनों स्तरों लोकसभा, राज्य वधानसभाओं और स्थानीय नकियायों के लिये उपयोगी हो, तार्का दोहराव और त्रुटियों को कम कयिा जा सके।
  - मतदाता सत्यापन और परणामों के सारणीकरण समेत चुनावी प्रक्रियाओं के कुशल प्रबंधन के लिये प्रौद्योगिकी का उपयोग करना।
  - चुनाव आयोग की सफ़िरशों (2016) में मतदाता पंजीकरण और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के लिये प्रौद्योगिकी के उपयोग सहति चुनावी प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने के लिये परविरतनों का सुझाव दयिा गया था।
- **जन जागरूकता अभियान:** मतदाताओं को एक साथ चुनाव कराने के लाभों और उनके मतदान अनुभव पर इसके प्रभाव के बारे में सूचित करने के लिये देशव्यापी अभियान शुरू करना।
  - प्रस्तावति परविरतनों पर सूचना प्रसारति करने और जनता से फीडबैक एकत्र करने के लिये सरकारी संगठनों तथा सामुदायिक संगठनों को शामिल करना।
- **क्षमता नरिमाण:** सुचारु कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिये एक साथ चुनावों से जुड़ी नवीन प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं पर चुनाव अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण सत्र आयोजति करना।

### दृष्टि भेन्स प्रश्न

प्रश्न: भारत में 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' को लागू करने के नहितार्थों का आलोचनात्मक वश्लेषण कीजयि। क्षेत्तीय प्रतनिधित्व और प्रशासनिक दक्षता से संबंधति चुनौतियों का भी उल्लेख कीजयि।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वरष के प्रश्न (PYQs)

????????

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2017)

1. भारत का नरिवाचन आयोग पाँच सदस्यीय नकियाय है।
2. संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनावों दोनों के लिये चुनाव कार्यक्रम तय करता है।
3. नरिवाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के वभिजन/वलिय से संबंधति वविाद नपिटाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) केवल 3

उत्तर: (d)

??????

प्रश्न. आदर्श आचार-संहति के उद्भव के आलोक में, भारत के नरिवाचन आयोग की भूमिका का वविचन कीजयि। (मुख्य परीक्षा, 2022)

